

प्रेषक,

भास्करानन्द,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 12 अप्रैल, 2013

विषय:- श्री उपेन्द्र जिन्दल पुत्र श्री महावीर प्रसाद जिन्दल, नई दिल्ली को टूरिज्म/इको रिसोर्ट्स के निर्माण हेतु जनपद नैनीताल के तहसील कोश्याकुटौली, पट्टी पाडली, ग्राम बुढलाकोट के अन्तर्गत कुल 0.280 है० भूमि क्रय करने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-741/12-जेड०ए०सी०/2012 दि०-23.11.2012 एवं पत्र संख्या-1006/12-जेड०ए०सी०/2012 दि०-18.3.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, श्री उपेन्द्र जिन्दल पुत्र श्री महावीर प्रसाद जिन्दल, नई दिल्ली को टूरिज्म/इको रिसोर्ट्स के निर्माण हेतु तहसील कोश्याकुटौली, पट्टी पाडली, ग्राम बुढलाकोट के अन्तर्गत आपके द्वारा संस्तुत खाता सं०-88 एवं 164 मध्ये 0.280 है० भूमि क्रय करने की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003, दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(II) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (टूरिज्म/इको रिसोर्ट्स के निर्माण) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।
- 3- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

*[Signature]*



- 5- शासन द्वारा दी गई भूमि क़य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 6- यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि क़य हेतु प्रस्तावित भूमि समस्त वर्जनाओं से विमुक्त है तथा संबंधित भूमि के क़य में किसी भूमि संबंधी कानून विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है।
- 7- सम्बन्धित क्षेत्र/भूमि की भूगर्भिक दशा एवं परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव के अध्ययन/आंकलन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 8- सम्बन्धित भूमि व उस पर प्रस्तावित निर्माण के सन्दर्भ में वन संरक्षण अधिनियम/वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एफ0ए0आर0 रूल्स अथवा अन्य कोई अधिनियम/नियम लागू होने/न होने तथा प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी किन्हीं विनियमों के परिप्रेक्ष्य में वांछित कार्यवाही/अनुपालन सम्बन्धित निवेशक/फर्म द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- परियोजना प्रस्ताव में दर्शित इकाई के डिजाइन, आकार/प्रकार, निवेश सीमा, निर्माण अवधि एवं अन्य संगत प्राविधानों/अभिकथनों का निवेशक द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाई में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।
- 11- इकाई के कैम्पस के अन्तर्गत पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- 12- यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि भूमि क़य एवं उस पर पर्यटन इकाई की स्थापना तथा इकाई द्वारा जल व अन्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने पर स्थानीय समुदाय/पंचायत को कोई आपत्ति न हो।
- 13- स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाई में स्थानीय युवकों/बेरोजगारों को रोजगार दिया जायेगा।
- 14- किसी दशा में प्रस्तावित क़ेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क़य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 15- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 16- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 17- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

*Below*

18- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझे, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जनपद स्तर से निर्गत होने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन की स्थिति से भी यथा समय पर शासन को अनिवार्य रूप से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)

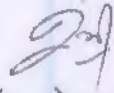
सचिव।

प्र०प०सं०- /समदिनांकित 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 5- श्री उपेन्द्र जिन्दल पुत्र श्री महावीर प्रसाद जिन्दल, निवासी आर.जेड. 82, मानस कुंज, उत्तम नगर, नई दिल्ली 59
- 6- निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- नोडल आफिसर/स्टॉफ ऑफिसर, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 8- प्रभारी मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(सन्तोष बडोनी)  
अनुसचिव।